

श्रीमती लता प्रसाद कलकत्ता कानून-मंत्रालय

फर्द अहकाम

उ
नं

बनाम भूला

अलय

854/2008

दिनांक आदेश या कार्यवाही	आदेश विस्तृत रूप से
27/9/2022	<p>पत्राकली प्रस्तुत। उपरोक्त अधिवक्तागण उपस्थित। वार का उपश्रम होने के कारण वार खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय बड़िही प्रथम से लिखवाया गया। पत्राकली फैसल शुद्ध होकर दायित्व दस्ता है।</p> <p>सहायक कलेक्टर बानेर न. जयपुर</p>



डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी: श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

वाद संख्या - 854/2008

वाद प्रस्तुति दिनांक - 21.12.1998

1. भैरू
2. रामपाल

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम अनोपपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..... वादीगण

बनाम

1. मूला पुत्र भूरा जाति जाट निवासी ग्राम अनोपपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. शंकर पुत्र रमसू जाति जाट, निवासी ग्राम अनोपपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत दुरुस्ती, इन्द्राजात,घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम - 1955
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 9 सपटित धारा 151
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम

वाद का उपशमन हो जाने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्ताख्त व मुहर अदालत से आज

रीख 27.09.2022 को जारी किया।



सहायक क्लर्क
आमेर
जयपुर

क्र.सं.	विवरण	पैसे	मुकद्दाम/विवरण	रुपये	विवरण
1	सहायक क्लर्क	2 रुपये	सहायक क्लर्क	2 रुपये	
2	सहायक क्लर्क	2 रुपये	सहायक क्लर्क	2 रुपये	
3	सहायक क्लर्क		सहायक क्लर्क		
4	सहायक क्लर्क		सहायक क्लर्क		
5	सहायक क्लर्क		सहायक क्लर्क		
6	सहायक क्लर्क		सहायक क्लर्क		
7	सहायक क्लर्क		सहायक क्लर्क		
8	सहायक क्लर्क		सहायक क्लर्क		
9	सहायक क्लर्क		सहायक क्लर्क		
10	सहायक क्लर्क		सहायक क्लर्क		
11	सहायक क्लर्क		सहायक क्लर्क		
12	सहायक क्लर्क		सहायक क्लर्क		
13	सहायक क्लर्क		सहायक क्लर्क		
14	सहायक क्लर्क		सहायक क्लर्क		
15	सहायक क्लर्क		सहायक क्लर्क		
16	सहायक क्लर्क		सहायक क्लर्क		
17	सहायक क्लर्क		सहायक क्लर्क		
18	सहायक क्लर्क		सहायक क्लर्क		
19	सहायक क्लर्क		सहायक क्लर्क		
20	सहायक क्लर्क		सहायक क्लर्क		

न्यायालय :- सहायक कलेक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)



पीठासीन अधिकारी : श्रीमती अपर्णा शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित आवेद संख्या 854 / 2008 दिनांक 27/12/1998

1. प्रेष

2. समाप्त

अपराध जाति आठ निवासी ग्राम अनूपपुर तहसील आमेर जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. राजेश कुमार मुसा जाति आठ निवासी ग्राम अनूपपुर तहसील आमेर जिला जयपुर
2. राजेश कुमार समसु जाति आठ, निवासी ग्राम अनूपपुर तहसील आमेर जिला जयपुर
3. राजेश कुमार समसु जाति आठ तहसीलदार आमेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद बाबत दुरुस्ती, इन्द्राजात, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम - 1955

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 9 संपटित धारा 151

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम

उपस्थिति -

1) श्री बशीधर जाट - अधिवक्ता वादीगण

2) श्री घीसाजाल कुमावत - अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से

दिनांक - 27/09/2022

निर्णय

1. राजेश कुमार मुसा जाति आठ निवासी ग्राम अनूपपुर तहसील आमेर जिला जयपुर
2. राजेश कुमार समसु जाति आठ, निवासी ग्राम अनूपपुर तहसील आमेर जिला जयपुर
3. राजेश कुमार समसु जाति आठ तहसीलदार आमेर जिला जयपुर
विरुद्ध
1. श्री बशीधर जाट - अधिवक्ता वादीगण
2. श्री घीसाजाल कुमावत - अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से
काश्तकारी अधिनियम - 1955 के अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं 9 संपटित धारा 151
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के अंतर्गत
आदेश 22 नियम 4 एवं 9 संपटित धारा 151 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के अंतर्गत
आदेश 22 नियम 4 एवं 9 संपटित धारा 151 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के अंतर्गत
आदेश 22 नियम 4 एवं 9 संपटित धारा 151 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के अंतर्गत

सहायक कलेक्टर
आमेर

प्रतिवादी संख्या 1 मूला के कायम मुकामान की ओर से जवाब प्रार्थना में अंकित किया है कि वादीगण का यह कथन की प्रार्थी अधिवक्ता से प्रार्थी का संपर्क नहीं हो सका इस कारण समय सीमा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। क्योंकि वादीगण का अपने अधिवक्ता से लगातार संपर्क रहा है। अधिवक्ता वादी के पास वादी के फोन नम्बर रहे है। दोनों के पास फोन होना व्यवहारिक भी है। प्रतिवादी ने रथाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है जो प्रस्तुत वाद के कन्सोलिडेट किया जा चुका है जिसमें प्रतिवादी द्वारा कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र अलग से पेश करने की आवश्यकता नहीं है। कानूनन व न्यायनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लेने की समय सीमा बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है, जिस कारण संपूर्ण वाद अबेट हो चुका है। प्रार्थना पत्र अवधि बाहर पेश किया गया है इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व सम्पूर्ण वाद अबेट होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः कानूनन सेटसाईड नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा प्रतिवादी के अधिवक्ता ने वादीगण के अधिवक्ता को प्रतिवादी संख्या 1 के स्वर्गवास की सूचना दे दी थी जिसका स्पष्ट अंकन न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.03.2016 में है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लेने व अबेटमेण्ट को निरस्त करने हेतु दिनांक 24.10.2016 यानी 17 माह बाद प्रस्तुत किया है जो की अवधि बाहर है। अतः सम्पूर्ण वाद स्वतः ही अबेट हो चुका है।



विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षों के बीच हुई। जिन्होंने उन्हीं तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये है। हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षों की बहस व न्यायिक दृष्टान्तो पर मगन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण के कथनानुसार प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 02.05.2015 को हो गई थी तथा वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लेने व अबेटमेण्ट को निरस्त करने हेतु आवेदन 1 वर्ष 5 माह बाद प्रस्तुत किया है जो कि अन्दर गियाद/अवधि प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी ने देश से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु पर निर्धारित अवधि में प्रार्थना पत्र पेश ना होने पर वाद स्वतः उपशमित हो गया है। वादीगण ने पूर्ण जानकारी के उपरान्त भी जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसमें ना तो आवेदन प्रस्तुत करने में हुए पिलग्व को क्षमा किये जान हेतु कोई युक्तियुक्त एवं विश्वसनीय कारण अंकित नहीं किये है। साथ ही प्रतिवादीगण की आपत्ति का खण्डन भी वादीगण द्वारा नहीं किया है। जहां विधि द्वारा परिशीलित समय के भीतर कोई आवेदन नहीं किया जाता है वहां आवेदन को गुणावतुण पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। देश के कारण संतोषप्रद ना होने से वाद को स्वतः अबेट हुआ मानना आवश्यक है। यह कानून का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्यायालय न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में किसी दूसरे पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वाद को

प्रमुख न्यायाधीश
अधीक्षक न्यायाधीश

उपशमन होने के परिणाम स्वरूप प्रतिवादी पक्ष के हित में कानूनी बिन्दू सृजित हो गया है। जिसे सरसरी तौर पर या विधिक प्रावधानों के विपरित उससे नहीं छीना जाना चाहिए। इस प्रकार वादी पक्ष द्वारा आदेश 22 नियम 4 व 9 का प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करने से वाद स्वतः उपशमित हो गया है। तथा जैसा कि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त 2010 (2) RRT 1437, 2017 (1) RRT 117, 2019 RPI - 61 जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यदि वाद का उपशमन प्रतिवादी के विरुद्ध ही माना जाता है तो प्रतिवादी के वारिसों के रिकॉर्ड पर ना आने से सहस्वामित्व की विरोधाभासी डिक्रीया पारित होने की संभावना है। अतः सम्पूर्ण वाद अबेट होने योग्य है। ऐसी परिस्थितियों में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गंभीर लापरवाही तथा वैधानिक प्रावधानों के विपरित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुये वाद का उपशमन हो जाने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है।



सहायक कोलक्टर
आमेर न्यू जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कोलक्टर
आमेर न्यू जयपुर